Krishi Kumbh
Www.KrishiKumbh.Com
कृषि कुंभ
E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 04 भाग 01, (जुन, 2024)
पृष्ठ संख्या 59–61

भारतवर्ष में दुग्ध उत्पादनः एक परिदृष्य एवं संम्भवनायें

डॉ0 महेन्द्र पाल[1], डॉ0 रवीन्द्र कुमार[2], डॉ0 डी0 के0 महतो[3], डॉ0 आर0 के0 सुहाने4, डॉ0 एस0 आर0 पी0 सिंह5 एवं डॉ0 पंकज कंमार6

[1]सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक उधान (फल), जूट अनुसंधान संस्थान, कटिहार, बिहार
[2]ए0 जी0 एम0 प्रोडक्सन, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, गुलाबबाग, पूर्णिया, बिहार
[3]सह–निदेशक अनुसंधान, आर0 आर0 एस0, अगवानपुर, सहरसा, बिहार
[4]निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविधालय, सबौर, भागलपुर, बिहार
[5]सहायक प्राध्यापक–सह–कनीय वैज्ञानिक (सब्जी एवं पुष्प उत्पादन, बी0 पी0 एस0 ए0 सी0,पूर्णिया, बिहार
[6]विषयवस्तु विशेषज्ञ (प्रसार शिक्षा), कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार, बिहार भारत।

Email Id: –gangwar.mahendra@rediffmail.com

सारांशः

भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, जिसका विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 24 प्रतिशत का योगदान है, परन्तु प्रति पशु उत्पादकता अन्य देशो की अपेक्षा बहुत कम एवं प्रति व्यक्ति औसत दुग्ध उपलब्धता 445 ग्राम हैा देश के मुख्य दुग्ध उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा आँध्र प्रदेश है आई0 सी0 एम0 आर0 द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध की आवश्यकता 370 ग्राम होती है। जबकि भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता औसत से बहुत कम है, जिसके मुख्य कारण उन्नत नस्ल, आहार एवं चारा, पशु स्वास्थ सेवाओ की कमी है इस कारण से क्षेत्र की वर्तमान समस्याओ एवं आवश्यकताओ को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर पालन एवं पशु आहार व चारा बीज उत्पादन में रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत अनुदान पशुधन विकास योजना अंतर्गत दिया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आहार एवं चारा बीज उत्पादन में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित एवं दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में भी चलाये जा रहे है।

प्रस्तावना

भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है और वर्ष 2021–22 में रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन 22 करोड़ टन हुआ है एवं विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 24 प्रतिशत योगदान के साथ पहले स्थान पर पहुच चुका है। विगत 10 वर्षो में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 51 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। जिसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का है। आज सीधे तौर पर 8 करोड़ किसान पशुपालन से जुड़कर लाभकारी योजना का लाभ ले रहे है मनुष्य जीवन में कृषि के साथ पशुपालन का सम्बन्ध मानव

सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हुआ है कृषि एवं पशुपालन एक सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रो में विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानो तथा भूमिहीन मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाने का साधन हैस ग्रामीण क्षेत्रो में 80 प्रतिशत से अधिक परिवार अपने घरो में पशुधन रखते है, डेरी एवं पशुपालन से छोटे एवं सीमांत किसानो की कुल आय का लगभग 35: तक प्राप्त होता है। पशुपालन का व्यवसाय अन्य क्षेत्रो की तुलना में कम से कम निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रो में आय का साधन है।

भारत में दूधः एक नजर

भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में 24 प्रतिशत योगदान के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है जसमे देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य जैसे राजस्थान (15.05 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (14.93 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (8. 06: प्रतिशत, गुजरात (7.56 प्रतिशत) और आँध्र प्रदेश (6.97 प्रतिशत) अग्रणी भूमिका निभा रहे है परन्तु प्रति पशु उत्पादकता अन्य देशो से काफी कम है देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कुछ राज्यों में जैसे पंजाब (1271 ग्राम), राजस्थान (1150 ग्राम), हरियाणा (1081 ग्राम), आदि में राष्ट्रीय दुग्ध उपलब्धता औसत (445 ग्राम) से काफी अधिक है, परन्तु अधिकांश राज्यों में जैसे असम (77.00 ग्राम), अरुणाचल प्रदेश (82 ग्राम), पश्चिम बंगाल (179 ग्राम), झारखण्ड (187 ग्राम) एवं बिहार (270 ग्राम) और दिल्ली एवं उत्तर–पूर्वी राज्यों में तो यह 100 ग्राम से भी कम है जोकि आई0 सी0 एम0 आर0 की सिफारिश प्रति व्यक्ति दुग्ध आवश्यकता (370 ग्राम) से काफी कम है। जिसके प्रमुख कारणों में उन्नत नस्ल के पशुओ की कमी, अच्छी गुणवत्ता के हरा व सूखा चारा का अभाव, दुग्ध उत्पादन के आधार पर संतुलित आहार न मिलना, बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाओ की कमी आदि शामिल है।

प्रति व्यक्ति दुग्ध आवश्यकता (370 ग्राम) से काफी कम है। जिसके प्रमुख कारणों में उन्नत नस्ल के पशुओ की कमी, अच्छी गुणवत्ता के हरा व सूखा चारा का अभाव, दुग्ध उत्पादन के आधार पर संतुलित आहार न मिलना, बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाओ की कमी आदि शामिल हैस इस कारण से क्षेत्र की वर्तमान समस्याओ एवं आवश्यकताओ को देखते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा एवं देसी नस्लों के संरक्षण एवं नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादकता बढाने के उद्देश्य से कल्याणकारी पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (2021–22) क्या है?

राष्ट्रीय पशुधन मिशन मुख्य रूप से बैकयार्ड पोल्ट्री और छोटे जुगाली करने वाले पशु (बकरी और भेड़) पालन के साथ–साथ चारा संसाधन विकास और बीमा जैसे कुछ अन्य घटकों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (छस्ड) को क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओ को देखते हुए योजना को संसोधित एवं पुनर्व्यवस्थित कर वित्तीय वर्ष 2021–22 से सम्पूर्ण देश में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार का सृजन करना, उद्यमिता का विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि एवं मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है, इसके अतिरिक्त उत्पादन से घरेलु मांगो को पूरा करने के बाद निर्यात आय को बढ़ाना, असंगठित क्षेत्र

में उपलब्ध उपज के लिए आगे एवं पीछे की कड़ी बनाने और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमी को विकसित करना स यह मिशन पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में शामिल 10 करोड़ पशुपालको को अधिक लाभदायक बनाने के लिए संचालित किया जा रहा है।

मिशन के मुख्य उद्देश्य

छोटे जुगाली करने वाले पशु जैसे भेड़ व बकरी एवं चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन करना ।

- नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना।
- मांस, अंडा, बकरी दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि ।
- चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना तथा चारे एवं आहार की उपलब्धता बढ़ाना ।
- चारा प्रसंस्करण इकाइयो की स्थापना को प्रोत्साहित करना ।
- पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन के उपायों को बढ़ाना ।
- आहार एवं चारे की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसन्धान को बढ़ावा देना ।
- किसानो को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करना ।
- कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियो के प्रसार को बढ़ावा देना ।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उप–मिशन

मिशन को तीन मुख्य उप–मिशन में विभाजित किया गया है:–

उप–मिशन (क.) पशुधन एवं कुक्कुट नस्ल विकास इस उप–मिशन का उद्देश्य कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन को प्रोत्साहित करना एवं नस्ल सुधार के लिए उद्यमित्ता विकास हेतु और राज्य सरकार को नस्ल सुधार की अवसंरचना ढाचे के लिए भी तीव्र ध्यान देने का प्रस्ताव है। योजनावार पूंजीगत लागत पर अनुदान राशि का विवरण सारणी–1 में अंकित है।

सारणी:1 योजनावार पूंजीगत लागत पर अनुदान राशि

क्र सं	योजना	पूंजीगत लागत	अनुदान (50 %)
1.	मुर्गीपालन	50 लाख	25 लाख
2.	भेड़ एवं बकरी पालन	100 लाख	50 लाख
3.	सुअर पालन	60 लाख	30 लाख
4.	आहार व चारा विकास	100 लाख	50 लाख

धोषणा:–

उपयुक्त ऑकडे इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न बेवसाइटस से एकत्रित किया गया है। इस लेखक का उददे य सिर्फ जानकारी एवं ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना मात्र है। एवं समस्त लेखकगण अच्छी जानकारी अपलोड करने के लिए विभिन्न बेवसाइटस एवं सस्थानों को घन्यबाद देते है।